राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 1 ■ अंक 1 (प्रवेशांक) ■ मई, 2017 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32

आतंकवाद के ताबूत में कील साबित होगी फैयाज़ की हत्या 12

On the Verge of War : North Korean Missile Crisis 17

आप के पतन की बुनियाद में अरविन्द का अहंकार 25

परिषद्–गतिविधियाँ

सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों के श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम में सिलचर (असम) के कार्यकर्ता

गोवाहटी में आयोजित आरोहण कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते
अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के.एन. रघुनन्दन व अन्य अतिथिगण

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

व[redacted] अंक 1 (प्रवेशांक) ▪ मई, 2017

संपादक-मण्डल :
आशुतोष
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002.
फोन : 011-23216298
वेबसाइट : www.abvp.org

[redacted]hhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली-110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

CONTENTS

5 **नक्सलवाद का ख़ात्मा राष्ट्रवाद से ही सम्भव है – आशुतोष मण्डावी**
छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित सुकमा ज़िले में दिनांक 24 अप्रैल 2017 को हुए घातक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में हुए इस हमले के बाद नक्सलियों ने एक बार फिर...

- संपादकीय 4
- **ABVP to paid homage to the Martyrs of Sukma Attack** 9
- सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों को अभाविप ने दी श्रद्धाञ्जलि 10
- **ABVP protests against Muslim Reservation Bill in Telangana** 11
- **ABVP Assam organises AAROHAN-2017** 11
- आतंकवाद के ताबूत में कील साबित होगी फैयाज़ की हत्या – आशुतोष भटनागर 12
- **MeDeVision 2017 : All India Conference for Dental and Medical students** 15
- शैक्षिक अराजकता के ख़िलाफ़ अभाविप ने सौंपा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ज्ञापन 16
- **On the Verge of War : North Korean Missile Crisis — Abhishesk Srivastava** 17
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के ख़िलाफ़ अभाविप ने सौंपा ज्ञापन 19
- **ABVP gave memorandum to HRD Minister regarding Punjab University** 20
- **ABVP organises 'SAMAJIK ANUBHUTI' in Telangana** 21
- अभाविप के कार्यकर्ताओं ने किया सामाजिक जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव 22
- बीआईटी परिसर में 'छत्तीसगढ़ युवा संसद' का शानदार आगाज 22
- **Growing Naxalism and its Urban Connect — Dr. Ahishesk Tandon** 23
- आप के पतन की बुनियाद में अरविन्द का अहंकार – हर्षवर्धन त्रिपाठी 25
- **ABVP protests against Karnataka government's failure to tackle Law and Order** 29
- परिचर्चा : महापुरुषों के नाम पर अवकाश कितना सही ? 30

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

विकास की कुलाचें लगाते भारत की गुलाबी तस्वीर पर हिंसा का काला धब्बा गहराता जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत जिस भारत की पहचान के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, वह पूरा भूगोल नानाविध अतिवादी चुनौतियों से आक्रांत है।

उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष–विराम के उल्लंघन की बढ़ती घटनाएँ और पीछे से इसे शह देते चीन का साथ, कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथी इस्लाम का बढ़ता वर्चस्व, खालिस्तान की मांग को फिर से ज़िंदा करने की कोशिशें और उनका समर्थन करते मानवाधिकारवादी, मध्य भारत में नक्सलवाद की हिंसक घटनाओं में वृद्धि, दक्षिण में पैर पसारता आईएसआईएस का जाल और इस्लामिक दहशतवाद का उभार, केरल में वामपंथी हिंसा का नित नया प्रकरण और इन सबको सैद्धान्तिक आधार और क़ानूनी सहायता देते दिल्ली सहित अन्य महानगरों में जमे इनके ओवरग्राउंड कार्यकर्ता बुद्धिजीवी।

यह देखना सुखद है कि भारत में दशकों बाद एक ऐसा राष्ट्रवादी उभार आकार ले रहा है जिसमें आम नागरिक स्वेच्छया अपनी भूमिका निभा रहा है। उपर्युक्त प्रत्येक भारतविरोधी शक्ति को इस उबार में अपने अस्तित्व के लिए संकट की छाया दिख रही है। इसे स्वीकार करते हुए इन सभी शक्तियों ने अपने परस्पर वैर और वैचारिक मतभेदों को किनारे कर हाथ मिला लिया है। राष्ट्रीय चिन्तन को अपना आदर्श माननेवाले सभी समूहों के समक्ष यह साझा चुनौती है जिसका मिलकर सामना करना होगा।

एक ओर जहाँ देश के भीतर स्थित कुछ शक्तियाँ इस राष्ट्रवादी उभार के साथ कदम मिलाने में अपने–आप को असमर्थ पा इसे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं विश्व–रंगमंच पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता के विरुद्ध भी सीमावर्ती देश एकजुट हैं। चुनौती भीतर से भी है और बाहर से भी। ऐसी स्थिति में पिछले अनुभव से सीख लेकर, तथ्यों और तर्कों के पैमाने पर कसकर समग्र राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की ज़रूरत है। यह नीति भीतरी और बाहरी चुनौतियों का मुक़ाबला करते हुए विकास के नये आयामों को स्पर्श करने तथा राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा को संबोधित करनेवाली होनी चाहिये।

देश के सामने यह उद्योगपर्व है जिसमें सभी नागरिकों की यथायोग्य भूमिका आवश्यक है। युवा भारत के प्रतिनिधि छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की भी अपनी एक सुनिश्चित भूमिका है। इस माह के अंत में होनेवाली अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् में इन विषयों पर सदैव की भाँति विस्तार से चर्चा होगी और भविष्य की योजना भी बनेगी।

सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं से निवृत्त होकर आगामी योजनाओं पर विचार कर रहे होंगे। भारतीय चिन्तन के अनुसार जिस सनातन यात्रा में सहयात्री होने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसे गहराई से समझकर पूर्णता को प्राप्त हों, इस हेतु एक विचारोत्तेजक लेख इस अंक में संग्रहीत है। इस अंक से 'छात्रशक्ति' में हिंदी के साथ ही अंग्रेज़ी में भी सामग्री उपलब्ध रहेगी, जिससे दक्षिण के राज्यों तक सूचना और संवाद का प्रवाह अबाध हो सकेगा।

हार्दिक शुभकामना सहित,

आपका,

संपादक

आवरण-कथा

नक्सलवाद का ख़ात्मा राष्ट्रवाद से ही सम्भव है

■ आशुतोष मंडावी

छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित सुकमा ज़िले में दिनांक 24 अप्रैल 2017 को हुए घातक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में हुए इस हमले के बाद नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी कुत्सित मानसिकता का अहसास कराया है जो भारतीय लोकतन्त्र के लिए एक काला धब्बा है। पिछले कुछ सालों से नक्सलियों ने हज़ारों की संख्या में सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान तथा आम ग्रामीण नागरिकों को अपना शिकार बनाया है, और पिछले कई वर्षों से वे सरकार को खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक हुए बड़े नक्सली हमलों की यदि बात करें तो पिछले 10 साल में नक्सलियों ने कई बड़े हमलों को अंज़ाम दिया जिसमें हज़ारों की संख्या में आम जनता व पुलिसवाले मारे गए। गत 9 जुलाई, 2007 को एर्राबोर के नक्सली-हमले में 23 पुलिसकर्मी शहीद हुए, दिनांक 15 मार्च, 2007 में बीजापुर के रानीबोदली में पुलिस के 55 जवान शहीद हुए, दिनांक 29 जून, 2010 को नारायणपुर जिले के धौड़ाई में 27 जवान शहीद हुए, 17 मई, 2010 को 12 पुलिस अधिकारियों सहित 36 लोगों को नक्सली हमले में जान गँवानी पड़ी थी; 26 अप्रैल, 2010 को बीजापुर जिले की घाटी में बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 जवान शहीद हो गए थे; 16 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर बारूदी सुरंग लगाकर विस्फोट के बाद गोलीबारी की थी जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे; जून 2011 में दन्तेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर लैंड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को उड़ा दिया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे; दिनांक 12 मई, 2012 को सुकमा के दूरसंचार केंद्र पर हमला हुआ, जिसमें चार जवान शहीद हुए; दिनांक 25 मई, 2013 को सुकमा जिले से परिवर्तन-यात्रा से लौट रहे काँग्रेसी नेताओं के काफ़िले पर

आवरण-कथा

विगत कुछ वर्षों में नक्सल-समस्या देश के करीब एक दर्जन से अधिक राज्यों में फैल चुकी है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक उनकी गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश घोर नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं।

जीरम घाट में घात लगाए नक्सलियों ने दरभा घाट में बारूदी सुरंग विस्फोट कर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें 28 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस घटना में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नन्द कुमार पटेल का अवसान हो गया था; 30 मार्च, 2016 को दंतेवाड़ा के मैलावाड़ा में आईईडी-विस्फोट में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हुए थे तथा 11 मार्च, 2017 को सुकमा जिले में इंजरम-भेज्जी मार्ग निर्माण को सुरक्षा प्रदान करने रवाना की गयी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 219वीं बटालियन से कोत्ताचेरू ग्राम में हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए एवं तीन अन्य गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गए थे तथा नक्सली काफ़ी मात्रा मे शहीद जवानों के हथियार लूटकर ले गए थे। अभी ताजा घटनाक्रम की यदि बात करें, तो दिनांक 24 अप्रैल, 2017, सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला कर दिया जिसमें 26 जवान शहीद हो गए। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यजनक है जो अब धीरे-धीरे नासूर बनता जा रहा है। अब इस नासूर को यदि समय रहते नहीं मिटाया गया, तो हमारे लोकतन्त्र के लिए वास्तव में संकट की स्थिति बन जाएगी।

विगत कुछ वर्षों में नक्सल-समस्या देश के करीब एक दर्जन से अधिक राज्यों में फैल चुकी है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक उनकी गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश घोर नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं।

दिनांक 24 अप्रैल, 2017, सोमवार को सुकमा में हुए हमले की रिपोर्टों के मुताबिक करीब 300 नक्सलियों ने दोपहर करीब 12:30 बजे सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला और 26 जवान शहीद हो गए। ज्ञात हो कि इस हमले के दौरान 300 नक्सलियों में करीब 70 प्रतिशत महिलाएँ भी शामिल थीं। जानकारी के मुताबिक चिंतागुफा के पास बुर्कापाल में नक्सलियों ने रोड-ओपनिंग के लिए निकली सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों पर घात लगाकर फायरिंग कर दी जिसमें मौके पर शामिल जवानों ने भी फायरिंग कर नक्सलियों को मुँहतोड़ ज़वाब दिया। पर अब सवाल यह है कि इस प्रकार की घटनाएँ आखिर कब तक चलती रहेंगी? क्या ये कभी थमने का नाम लेंगी?

नक्सलियों के द्वारा समय-समय पर किए गए इस दावे में जरा भी दम नहीं है कि स्थानीय जनता का उन्हें समर्थन प्राप्त है। बस्तर की आम नागरिक बस्तर का विकास चाहता है, परंतु बस्तर के जनजाति उनके भय के कारण ही उनका समर्थन करते हैं। नक्सली जिन संसाधनों के लिए अपनी लड़ाई का दावा करते हैं, उन्हीं को वे निशाना बनाते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि आम ग्रामीण जनता व आम जनजाति समाज नक्सली-ठेकेदार-नौकरशाह की तिहाड़ी का शिकार होते नज़र आते हैं। इसके कारण ही वे आज भी वहीं हैं जहाँ आज़ादी से पहले थे। नक्सल-प्रभावित इलाकों में आम आदमी नक्सली और सुरक्षाबलों की चक्की में पिस रहा है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर की यदि बात करें, तो यह क्षेत्र हमेशा से शांत व सौम्य क्षेत्र रहा है। यहाँ का जनजीवन हमेशा से बिलकुल सामान्य रहा है। परंतु इस नक्सलवाद ने इस शांत, सुंदर व मनोरम क्षेत्र को रक्तरंजित क्षेत्र बना दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 50 के दशक में पूरी तरह शान्ति स्थापित थी जो वर्ष 1973-74 तक रही, परन्तु इसके बाद वहाँ व्याप्त गरीबी और अशिक्षा के कारण नक्सलवाद पनपना शुरू हुआ। वहाँ व्याप्त ग़रीबी और अशिक्षा की वजह से वहाँ की पुलिस, प्रशासन व नक्सल– सभी बस्तर के जनजातियों को अंकगणित की इकाइयों की तरह इस्तेमाल करने लगे और वहाँ की जनजाति व आम जनता इस लड़ाई मे पिस रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि बस्तर में विकास-कार्यों की शुरूआत ही नहीं हुई, परंतु आज के इस पड़ाव में बस्तर कई कारणों से काफ़ी पीछे चला गया है और जिसका नाज़ायज फ़ायदा देशविरोधी ताक़तों ने समय-समय पर उठाया है। और इसके पीछे के सच को भी हमें जानना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति-बहुल राज्य है, यहाँ की जनजातीय जनसंख्या 32 प्रतिशत है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जाति-समूह शामिल हैं। इनकी सांस्कृतिक विशेषता अपने आपमें महत्त्वपूर्ण है, परंतु इस सांस्कृतिक विशेषता को पहला ख़तरा तब महसूस हुआ जब वर्ष 1949 में दक्षिण बस्तर में विभिन्न क्षेत्रों से बहुत-से लोग आकर बसे थे जो शायद वहाँ की जनजातीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सिद्ध हुई। उस समय बस्तर में शक्ति के तीन प्रमुख केंद्र थे– प्रथम माई दंतेश्वरी, दूसरे बस्तर के महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव तथा तीसरी वहाँ जनजातियों के मध्य प्रचलित घोटुल-प्रथा थी। इन तीनों ने जनजातीय समाज को आपस में जोड़े रखा था, जो इनके आस्था के सर्वोच्च प्रतीक थे। दिनांक 25 मार्च, 1966 को इन प्रतीकों में से एक प्रतीक महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव की षड्यंत्रपूर्वक गोलीबारी में हत्या कर दी। श्री गणपतलाल साव, जो महाराजा के सचिव थे, के अनुसार अंग्रेजों द्वारा सन 1910 में बस्तर में अपनी शिक्षा-व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गयी, जिसका बस्तर में पुरजोर विरोध हुआ। उसी समय बस्तर की क्रांति के रूप में विख्यात 'भूमकाल आन्दोलन' का भी ज़िक्र आता है, जो कहीं-न-कहीं इस विद्रोह की कड़ी से जुड़ता है।

बस्तर क्षेत्र के तमाम समस्याओं पर यदि ग़ौर करें, तो हम पायेंगे कि शिक्षा व स्वास्थ्य की पहुँच से दूर बस्तर के पिछड़ेपन के तीन बड़े कारण– पुलिस, व्यापारी व प्रशासन है; क्योंकि पुलिस व प्रशासन के बारे में यह प्रचलित है कि वे जनजातीय समाज के लोगों को डरा-धमकाकर मांस और शराब की मांग करते थे और नहीं देने पर उन्हें ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता था। वहीं व्यापारी नमक के बदले वहाँ के आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन हड़प लेते थे। शायद यही कारण था कि बस्तर-जैसे मनोरम, शांति के टापू पर नक्सलवाद दस्तक देता नज़र आ रहा था। यदि बस्तर आज थोड़ा-बहुत बचा है तो सरदार वल्लभभाई पटेल की वजह से, जो बस्तर स्टेट को भारत के 562 रियासतों में शामिल करने में सफल रहे, अन्यथा बस्तर की बैलाडीला पहाड़ी को हैदराबाद के निज़ाम ने खरीद लिया था जिसे कोरिया के राजा के हस्तक्षेप पर ही भंजदेव ने बचाया था, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर की यदि बात करें, तो यह क्षेत्र हमेशा से शांत व सौम्य क्षेत्र रहा है। यहाँ का जनजीवन हमेशा से बिलकुल सामान्य रहा है। परंतु इस नक्सलवाद ने इस शांत, सुंदर व मनोरम क्षेत्र को रक्तरंजित क्षेत्र बना दिया है।

आज बस्तर में खून की होली खेली जा रही रही है। कल तक शान्ति के टापू के रूप में स्थापित बस्तर में आज गोली की आवाज़ें गूंजने लगी है। भारत में नक्सलवाद का ख़ात्मा बस्तर के नक्सलवाद के ख़ात्मे पर ही टिका है। इस समय नक्सलवाद की कहर से देश के 16 प्रान्तों के लगभग 20 ज़िलों के 1,400 गाँव जूझ रहे हैं। ओड़ीशा के कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानन्द के सामाजिक आन्दोलन की वजह से तथा राजनन्दगाँव के मोहला-मानपुर क्षेत्र में सामाजिक अलख जगाने में भूमिका निभानेवाले लाल श्याम शाह की वजह से इस क्षेत्र में नक्सलवाद पुरवे में नहीं पनप पाया, इन्होंने इन क्षेत्रों में व्यसन-मुक्ति के आन्दोलन चलाये तथा शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किये। इसी तरह जशपुर के कैलास गुफा व बागीचा के क्षेत्रों में गहिरा गुरु का योगदान महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगायी। वर्ष 1952 में जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक उत्थान हेतु कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी जो निरंतर अभी भी जारी है। वर्ष 1966 में बस्तर के महाराजा प्रवीर चन्द्रभंजदेव की हत्या के लगभग 12 वर्ष बाद 1980 तक नक्सलवाद का कोई नामोनिशान नहीं था। उसके बाद नारायणपुर व ओरछा में वर्ष 1991-92 में पहली बार ग्राम जागरण अभियान चलाया गया। 2003 में गीदम का थाना लूटा गया, युम्नर का बाज़ार लूटा गया जिसमें पुलिस ने 13 ग्रामीणों को जेल में डाल दिया और उन्हें उनके पास पाए गए सामान की पावती दिखाने को कहा गया और

आवरण-कथा

ऐसा प्रचारित किया गया की यह बाज़ार जनजाति ने समाज ने लूटा है। इस घटना से जनजाति समाज आहत हुआ और सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव ताँती के नेतृत्व में लगभग 500 लोग इन्द्रावती नदी के उस पार नक्सलियों से उनके शिविरों में मिलने पहुँचे और नक्सलियों को उसके दूसरे दिन यह बताना पड़ा कि इस घटना में जनजाति समाज का कोई हाथ नहीं है। इसके बाद लगभग सौ गाँवों में ग्राम सुरक्षा समिति बनाई गई, जिसने नक्सलियों को गाँवों से बाहर का रास्ता दिखाया। 19 मई, 2005 को बस्तर के ग्रामीणों द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए चल रही बैठक में नक्सलियों के द्वारा 19 लोगों की हत्या की गई। इसी तरह 22 मई, 2005 को 5,000 ग्रामीणों की बैठक के दौरान भी हत्या का प्रयास नक्सलियों द्वारा किया गया, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा यह तय किया गया कि नक्सलवाद का मुक़ाबला सलवा जुडूम से किया जाएगा जो देश में इस तरह का पहला प्रयास था। सलवा जुडूम से काफ़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे कुटरू, ताडमेटला व भैरमगढ़ से हज़ारों की संख्या में जनजाति समाज जुड़ने लगा। सलवा जुडूम के प्रयास से नक्सली बेचैन हो उठे और सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं पर हमले करने शुरू कर दिये। सरकार ने जनजातियों की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में 24 शिविरों का निर्माण कराया, जिसमें 80-100 गाँवों से लगभग 52,000 लोग रहने आने लगे। पीएसओ व कोया कमांडो की दहशत भी लोगों में बढ़ने लगी, नक्सलियों का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। इससे समर्थित संगठन हैरान हुए और इसके खिलाफ़ षड्यन्त्र कर सुप्रीम कोर्ट में 19 याचिकाएँ लगाई गयीं। दिनांक 05 जुलाई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल से प्रशिक्षित सुदर्शन रेड्डी के द्वारा पीएसओ को निरस्त करने के याचिका पर बिना तहकीकात के सलवा जुडून के विरोध में एक आदेश सुनाया। इस निर्णय से नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में विपरीत माहौल बना जो निराशाजनक था।

अगले अंक में समाप्त...

(लेखक कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में विज्ञापन एवं जनसम्पर्क अध्ययन विभाग के अध्यक्ष हैं)

ABVP to paid homage to the Martyrs of Sukma Attack

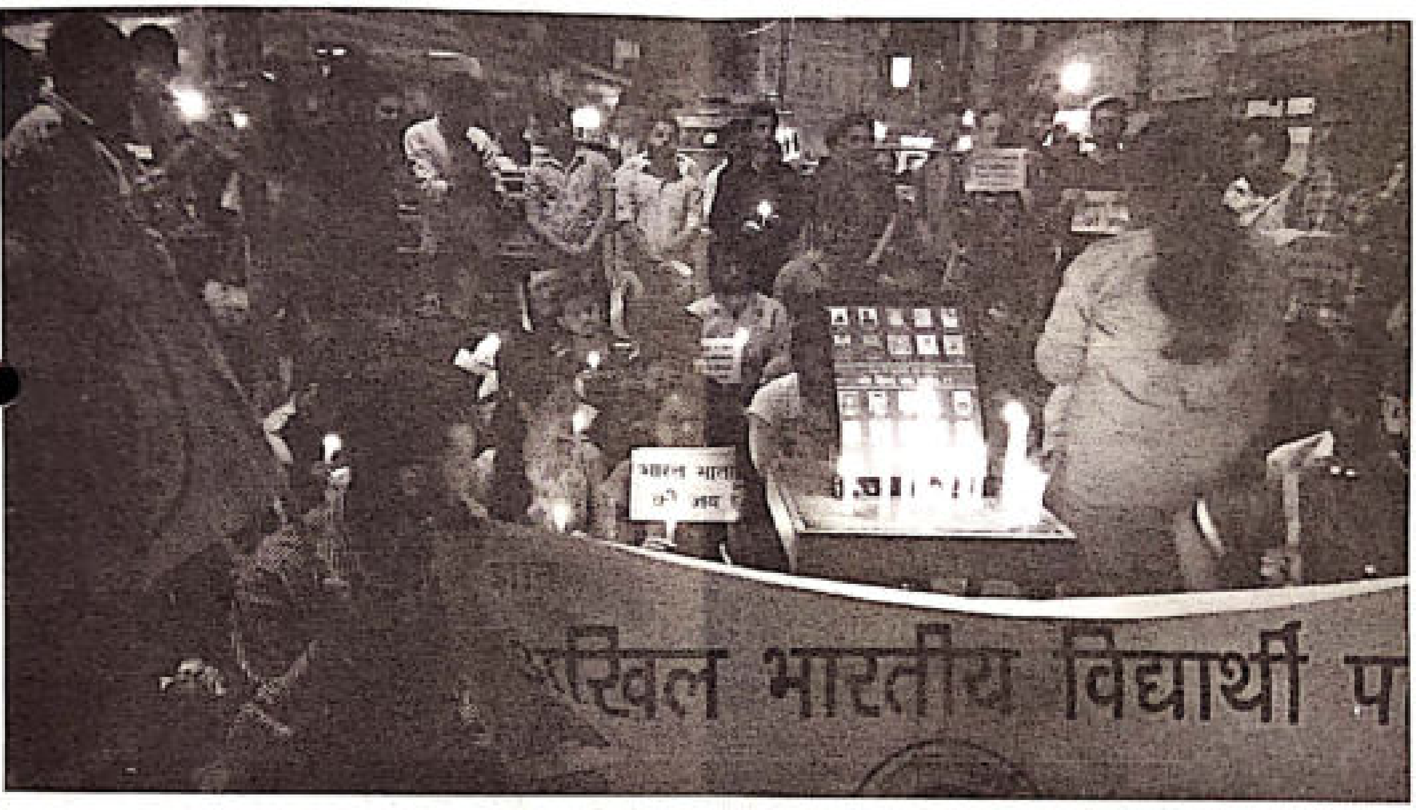

ABVP Jammu & Kashmir showing anguish and pain over the dastardly terror attack of Maoists on CRPF in which 25 soldiers were martyred. ABVP activists from various colleges and universities of the city took out a Candle March to pay homage to the martyrs and Saluted their martyrdom.

The Candle March started from Parade Chowk in the leadership of ABVP Jammu City Secretary Deepak Gupta and culminated at Kacchi Chhawni after passing through Moti Bazar. Activists participating in the march shouted slogans "Naxalvaad Murdabad", "Bharat Mata Ki Jai", "Vande Mataram" etc. At Kachhi Chawni, activists lighted candles, laid wreaths and observed silence for two minutes to remember the supreme sacrifice of 25 soldiers martyred at Sukma District of Chhatisgarh offered by Maoists. People from the civil society also participated and paid homage to the martyrs. Everyone urged Prime Minister Narendra Modi to give a befitting reply to the rogue Maoists.

Karnataka ABVP karyakartas paid homage to martyrs and prayed for soldiers injured and hospitalised. Ballary, hubli, kalaburgi, Bagalkot, mysuru, gouri bidanoor, chikkaballapur, and many places candle light march was organised. and coward attack. ABVP demand the Central govt to take a serious action against red terrorist. From more than 20 places 500 students participated. ■

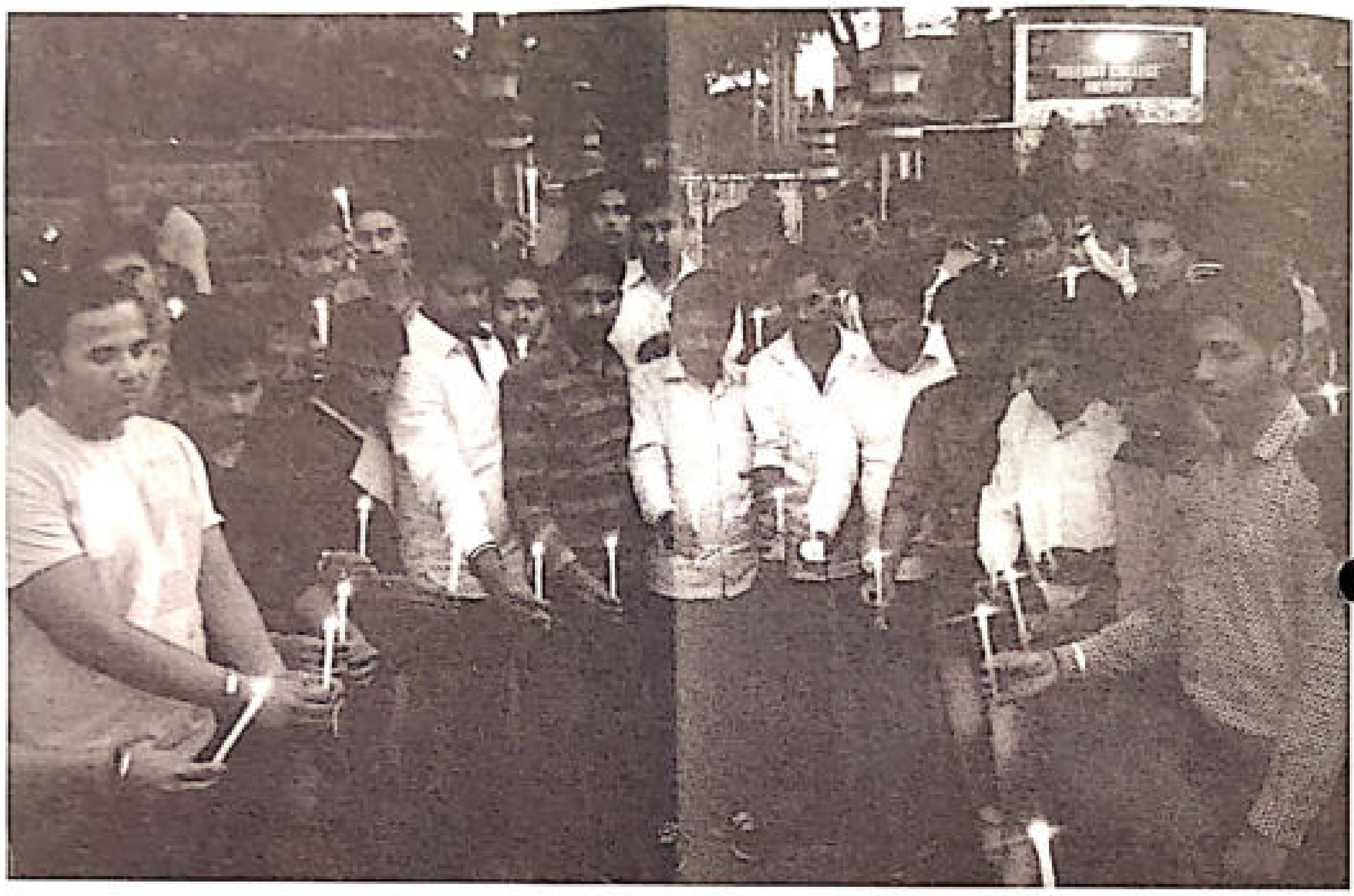

सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों को अभाविप ने दी श्रद्धाञ्जलि

अभाविप दिल्ली ने सुकमा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। श्रद्धाञ्जलि अर्पण कार्यक्रम नार्थ कैंपस के कला संकाय में किया गया, जिसमें 150 छात्रों ने भाग लिया। प्रदेश मंत्री भारत खटाना ने कहा कि जवानों पर हुआ हमला कायराना हरकत है, अब केंद्र सरकार को इन लाल वामपंथी आतंकियों को सबक सिखाने हेतु कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही जेएनयू में भी शहीद जवानों की शाहदत में श्रद्धाञ्जलि अर्पित की गयी।

अभाविप मेरठ द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धाञ्जलि दी गई। सुकमा-हमले में नक्सलियों के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर छिपकर अचानक हमला किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हुए एवम् दर्जनों जवान घायल हुए। अभाविप ने मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट मौन धारण किया। विभाग छात्रा प्रमुख नेहा काम्बोज ने कहा कि सुकमा नक्सलियों का गढ़ है अनेक बार नक्सलियों द्वारा ऐसे निन्दनीय आत्मघाती हमलों को अंज़ाम दिया गया है, जिसमें देश ने बहुत-से वीर सपूतों को खोया है। इस तरह की घटना बेहद कायरतापूर्ण है, अतः विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि नक्सलियों के खिलाफ़ कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही की जाए, यही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी। श्रद्धाञ्जलि अर्पित करनेवालों में विभाग संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार, जिला छात्रा प्रमुख हर्षिता सैनी भी उपस्थित रहे।

अभाविप पटना द्वारा सुकमा ज़िले में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धाञ्जलि सभा का आयोजन कारगिल चौक पर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमले राष्ट्र की अस्मिता पर चोट हैं, जिसका सरकार द्वारा तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। ■

ABVP protests against Muslim Reservation Bill in Telangana

ABVP Telangana organised a huge protest against the regressive Muslim Reservation Bill introduced by the Telangana State Assembly. The bill introduced on April 16th, 2017 grants 12% reservation to Muslims. A similar reservation bill was introduced by Congress too some time ago which was held unconstitutional by the Court.

Religion-based reservation results in unfair treatment of all, especially the economically backward classes of the society. ABVP has always opposed religion-based reservations which have the potential to result in division of the country and thus condemned the state government's move and has called for reservations based on social and economic status instead of religion.

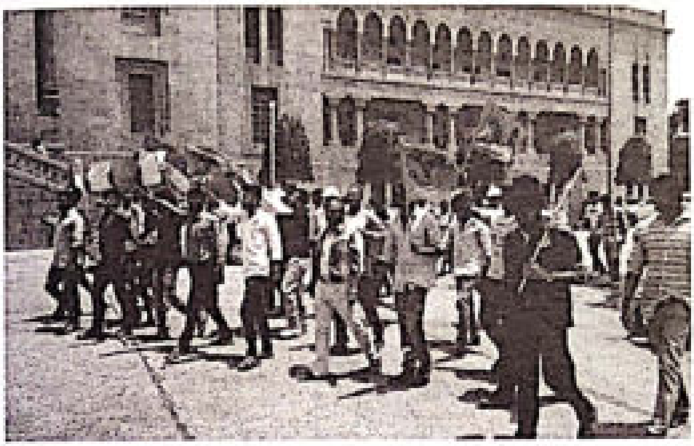

As a part of the protests, the ABVP activists burnt effigies of CM KCR and organized *'Rasta Rokos'* in several places through 16th-18th April. ABVP activists also tried to organize a *dharna* in front of the Chief Minister's camp office in Begumpet, protesting the proposed reservations based on religion but their attempts were thwarted by the police who later took them into custody. ■

ABVP Assam organises AAROHAN-2017

ABVP has been carrying out various activities in all parts of the nation for the development of students in the technical field. And as part of the above initiative, ABVP Assam organized a state-level Final Year Project Exhibition cum competition and technical paper presentation, named AAROHAN-2017. The exhibition and competition were held on the premises of the Assam Engineering College, Jalukbari, Guwahati on the 3rd & 4th of the month of May, 2017.

An opportunity for the finest and promising engineers of this state to come together to further the right engineering aptitude and professional competence, it comprised of the following:-

- Working Models of Final Year Engineering Projects
- Technical Paper Presentation Competition
- Hobby Project Competition
- Entrepreneurship Development Seminar

This is the first time that an exhibition of this scale has been organized in this part of the world. The delegates who attended the event included Dr. Anil Sahasrabudhe, Chairman, AICTE, Sri K N Raghunandan, National joint Organizing Secretary, ABVP, Er. Tana Nikam Tara, Member, AICTE (North East), Er. Tana Nikam Tara, Member, AICTE(North East), Er. Tana Nikam Tara, Member, AICTE(North East), Bhaveshwar Tombram, Director, Manipur Technical Education, P K Das, Director, Assam Software Technology Park Of India and Ganesh Turerao, Co-convener, Think India. The winners were felicitated and awarded exciting prizes and the event concluded successfully. ■

आतंकवाद के ताबूत में कील साबित होगी फैयाज़ की हत्या

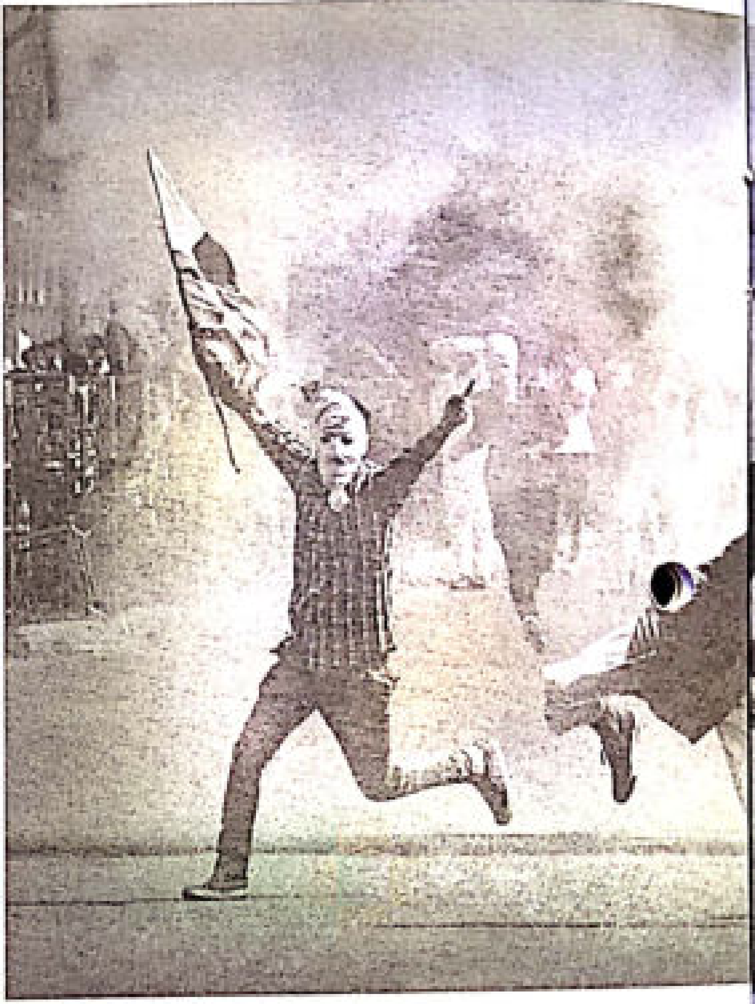

■ आशुतोष भटनागर

व्यक्तियों की तरह विचार भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मरते भी हैं। विचार जब तक मूल्यों और मानवीय सरोकारों के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। इनसे संबंध टूटने के साथ ही वे पतन की ओर बढ़ने लगते हैं और अंततः अप्रासंगिक हो जाते हैं। कश्मीर में पैदा हुए कथित आजादी के आंदोलन के साथ यही हो रहा है।

अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, तत्कालीन भारतीय नेतृत्व की अदूरदर्शिता और स्थानीय नेतृत्व की अतिमहत्त्वाकांक्षा की कोख में पला कथित आज़ादी का यह आंदोलन अपनी धार तब खो बैठा जब इसने अपने सूत्र पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिये। हाल में एक ऐसा मोड़ आया जब अलगाववादियों ने संसदीय दल के सदस्यों की संवाद की पहल को नकार दिया और सामान्य शिष्टाचार को भी त्यागकर विपक्षी नेताओं के लिये दरवाजे नहीं खोले।

उल्लेखनीय परिवर्तन तब हुआ जब आज़ादी की मांग करनेवाले यह कथित आंदोलनकारी अपना चोला बदलकर इस्लामी जेहाद की बात करने लगे। बुरहान वानी और उसके उत्तराधिकारी ज़ाकिर मूसा ने जेहाद की राह में आनेवाले सुरक्षाबलों के परिवारीजनों को भी मारने का ऐलान कर दिया वहीं गिलानी-जैसे अलगाववादी नेता मुठभेड़ में मारे जानेवाले आतंकियों की मौत को जेहाद में शहादत बताने लगे।

दस मई को शोपियां में भारतीय सेना में हाल ही में शामिल हुए युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की एक पारिवारिक समारोह में भाग लेते समय अपहरण कर की गई हत्या निश्चित रूप से वह मोड़ है जो पाकिस्तान-प्रेरित इस आतंकवाद के ताबूत की कील साबित होगा।

लेफ्टिनेंट उमर फैयाज भारतीय सेना के एक होनहार युवा अधिकारी थे। भारतीय सेना के गुडविल स्कूल, जिसकी हाल ही में अलगाववादी नेता गिलानी ने कड़ी निंदा की थी, में पढ़ने के दौरान ही फैयाज की भारत और राष्ट्रीयता की समझ बनी थी। इसी दौरान उसने सेना की कार्यपद्धति को समझा और उससे प्रेरित हो

लेफ्टिनेंट उमर फैयाज भारतीय सेना के एक होनहार युवा अधिकारी थे। भारतीय सेना के गुडविल स्कूल, जिसकी हाल ही में अलगाववादी नेता गिलानी ने कड़ी निंदा की थी, में पढ़ने के दौरान ही फैयाज की भारत और राष्ट्रीयता की समझ बनी थी। इसी दौरान उसने सेना की कार्यपद्धति को समझा और उससे प्रेरित हो स्वयं भी सेना से जुड़ने का संकल्प लिया। 96 प्रतिशत अंकों के साथ माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद उसके सामने कॅरियर सँवारने के अनेक विकल्प खुले थे, किन्तु उसने भारतीय सेना को चुना।

स्वयं भी सेना से जुड़ने का संकल्प लिया। 96 प्रतिशत अंकों के साथ माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद उसके सामने कॅरियर सँवारने के अनेक विकल्प खुले थे, किन्तु उसने भारतीय सेना को चुना। 2012 में उसका चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हुआ।

जब बुरहान वानी सुरक्षाबलों में शामिल कश्मीरी नौजवानों और उनके परिवारीजनों के लिए धमकीभरे वीडियो जारी कर रहा था, लगभग उसी समय फैयाज कश्मीरी युवाओं से पत्थरबाजी से दूर रहने और अमन बनाए रखने की अपील कर रहा था। यह सब करते हुए उसे भी यह अहसास रहा होगा कि इससे खतरा हो सकता है किन्तु यह इतनी जल्दी और इतना नृशंस होगा, यह शायद फैयाज ने भी नहीं सोचा होगा।

कुलगाम के सरसुरु गाँव का निवासी फैयाज राजपुताना रायफल में कमीशन प्राप्त करने के बाद पहली बार छुट्टी पर अपने घर आया था। अपने मामा की लड़की की शादी में भाग लेने के लिये शोपियां पहुँचने के एक घंटे बाद ही कुछ लोग उसे खोजते हुए आये और उसके एक पुराने दोस्त से मिलने की बात कहकर बाहर ले गये। इसके बाद अगले दिन सुबह गोलियों से छलनी उसका शव हरमैन गांव में मिला। शव पर पाए गए चोट के निशान बताते हैं कि हत्या से पहले उसके साथ बर्बरता की गयी। उसके दाँत भी तोड़े गये थे। यह ठीक वही तरीका था जिसे पाकिस्तानी हमलावर पहले भी अपनाते रहे हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके परिवारीजन भी उसके अपहरण की सूचना पुलिस या सेना को देने का साहस नहीं कर सके। फैयाज की घटना अपने आप में पहली घटना नहीं है। जिहादी गतिविधियों में रुकावट डालने पर कश्मीरी सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को निशाना बनाने की जाकिर मूसा की चेतावनी के बाद कुलगाम में एक डीएसपी के घर पर हमला किया गया। शोपियां में एक एसपी और एक डीएसपी के घर में तोड़-फोड़ की। दो पुलिसकर्मियों को पीटा गया। बड़गाम में एक जेलर के बेटे की कार में आग लगाने के बाद उसे अपहरण कर ले गये। एक डीएसपी के मामा की हत्या भी की गयी। लेकिन पिछले दो दशकों में किसी समारोह से अपहरण कर निहत्थे कश्मीरी

सैन्यकर्मी की बर्बर हत्या की यह पहली घटना है।

उमर फैयाज की हत्या पाकिस्तान और उनके पिट्ठू आतंकियों के दुःसाहस ही नहीं बल्कि उनकी हताशा को भी दर्शाता है। बुरहान की मौत के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर माहौल बनाया गया कि स्थानीय आतंकियों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद नये आतंकियों की संख्या तीन अंकों में नहीं पहुंच सकी। तीस और चौदह आतंकियों के वीडियो सोशल मीडिया पर लोड करके इसे साबित करने की कोशिश की गयी। इन वीडियो को देख 'सेना के होश उड़े' जैसे शीर्षक भी मीडिया में वायरल कराने की कोशिश की गई, किन्तु वे अपेक्षित दवाब बनाने में सफल नहीं हुए।

इसके विपरीत सेना द्वारा 800 पदों पर भर्ती के लिये की गयी रैलियों में 19 हज़ार से ज्यादा कश्मीरी नौजवान आ जुटे। ग्राम सुरक्षा समितियों में और एसपीओ के रूप में हज़ारों युवा स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यही स्थिति अलगाववादी नेताओं, लश्करे तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन-जैसे आतंकी संगठनों और पाकिस्तान को भी हताश और विचलित किए हुए है। हिंसा का चालू दौर साबित करता है कि वे निराशा के गर्त में हैं, अपनी रणनीति को ध्वस्त होते देख वे इसे आखिरी लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं।

बुरहान वानी की मौत के बाद फैले आंदोलन की आग शांत भी नहीं हो पायी थी कि आंदोलन का एक नया दौर शुरू हो गया। यद्यपि इस आंदोलन में न पहले जैसी सूत्रबद्धता बची है और न ही वैसी तीव्रता, लेकिन कथित प्रतिरोधी पक्ष इसे किसी-न-किसी तरह ज़िंदा रखना चाहता है।

बुरहान की मौत के समय घाटी में यह चर्चा आम थी कि उसे आईएसआई ने ही योजनापूर्वक कागज़ी शेर बनाया और फिर उसकी मौत को भुनाया। न तो बुरहान और न ही उसके उत्ताधिकारी जाकिर मूसा ने किसी बड़ी वारदात को अंज़ाम दिया था। इसके विपरीत वे सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराते रहे हैं। माना यह भी जाता रहा है कि सोशल मीडिया के यह अकाउंट भी पाकिस्तान से ही संचालित होते हैं। लेकिन यह स्वीकार करना ही होगा कि कश्मीर घाटी में आज अराजकता का एक दौर चल रहा है जिसमें स्थानीय युवा शामिल है।

चिंता का एकमात्र कारण हाथों में पत्थर उठाए नौजवान नहीं हैं जिनमें अब युवतियाँ भी शामिल हो गई हैं। इससे बड़ी चिंता यह है कि उन्होंने अब आज़ादी का चोला उतार फेंका है और खुल्लम-खुल्ला खिलाफत के राज की घोषणा कर रहे हैं। बुरहान और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जाकिर मूसा के बयानवाले वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसकी गवाही देते हैं।

अलगाववाद की राजनीति करनेवाले गिलानी और मीरवाइज-जैसे लोग आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर जेहाद की वक़ालत करते समय भले ही इसे अपने रणनीतिक पैंतरे की तरह इस्तेमाल करते रहे हों, नयी पीढ़ी के 'स्मार्टफोन जेहादियों' ने उससे अपना नाता जोड़ लिया है। पाकिस्तान के विपक्षी नेता इमरान ख़ान द्वारा नवाज़ शरीफ पर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लादेन से पैसे लेने के आरोप ने इसकी पुष्टि की है।

जेहाद हो या आतंक, अलगाववाद हो या आज़ादी की मांग, इस्लामिक कट्टरवाद हो अथवा जम्मू कश्मीर की भू-सामरिक चुनौती, सभी के तार जाकर पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पाकिस्तान के निर्माण के समय जो वैर उत्पन्न हुआ वह नासूर के रूप में जम्मू कश्मीर में फूटा। समय पर इलाज़ करने के बजाय इसे बढ़ने दिया गया। न इसकी संवेदनशीलता को समझा गया और न ही रणनीतिक महत्त्व को। व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी की लहरों पर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक नैया डूबती उतराती रही। स्थानीय आकांक्षाओं पर 'दिल्ली' होने का अहंकार भारी पड़ा। आज जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है वह दशकों की नीतिगत असफलता का परिणाम है।

जम्मू कश्मीर केवल कश्मीर नहीं है। सारा कश्मीर अलगाववादी नहीं है, आतंक का समर्थक नहीं है। लेकिन जब बात मीडिया की हो तो ख़बर का तत्त्व रखनेवाली घटनाएँ चूंकि कश्मीर में होती हैं, इसलिये सारी चर्चा कश्मीर के इर्द-गिर्द सिमट जाती है। लेकिन यह याद रखने की ज़रूरत है कि आज कश्मीर में जो हो रहा है, वह कश्मीर पर आक्रमण नहीं बल्कि भारत पर आक्रमण है। संघर्ष कश्मीर की भूमि पर भले ही हो रहा हो, किन्तु वह भारत के विरुद्ध है। इसलिये इस संघर्ष को समाधान तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भारत की है। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसके एक अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में व्याप्त अराजकता को भारत के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना और समयबद्ध और चरणबद्ध ढंग से इसके निवारण के प्रयास करना समय की मांग है।

MeDeVision 2017 : All India Conference for Dental and Medical students

MeDeVision 2017, a Conference for Dental and Medical students all over India concluded at the D Y Patil University Campus in Panvel. At the valedictory session, Convener of MeDeVision Dr Subram Sanpareddy, Dr. Ravi Shukla, Prafulla Akant, President of D Y Patil University Dr Vijay Patil, All India Head of MeDeVision Yadunath Deshpande among many others, were present.

The three day conference witnessed participation of around 1000 students. The inauguration ceremony took place in the presence of Union Minister of Health and Family Welfare J.P. Nadda. He urged the students to work in the rural and poverty struck areas of Maharashtra and India. Apart from that, he urged the doctors to give preference to generic medicines to minimise the expenditure of the patients.

MeDeVision 2017 facilitated discussions on topics like Real Life Role Model, Doctor Patient Relationship, **Love Bharat - Serve Bharat** in its sessions. The sessions in this period enforced a different kind of point of view for the medical students present in this conference.

In the session called Real Life Role Model, guests like Dr Pratibha Athavale and Dr Avinash Saoji were interviewed by Dr Anand Nirgude who is the head of ABVP's Konkan Division. "The number of doctors and hospitals is considerably less because doctors do not like to serve in this region", stated Dr Pratibha Athavale sorrowfully and urged the students to come stay and serve in the area for a few days. Dr Saoji guided the students by saying that money should have a secondary place in our profession and that serving the people is the primary motive.

In the Love Bharat Serve Bharat session, ABVP's National Organizing Secretary Sunil Ambekar guided the students by saying that they must serve their nation through their profession by helping those who have limited medical resources. He said that this would accomplish two things - the people in these regions would be helped and the students will experience the culture of India.

Shree Akant urged the doctors to serve their people and the society that they are a part of. The conference also consisted of research paper presentation competition and poster presentation competition. Around 200 students registered for the same. The winners from each competition were declared on the last day of this conference. While the students were noticeably sad about the conference ending, they also knew that they were taking on a mission with them. ■

शैक्षिक अराजकता के खिलाफ अभाविप ने सौंपा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ज्ञापन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज और शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर योगी से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल

प्रदेश में व्याप्त शैक्षिक अराजकता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पाँच-सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री-आवास पर हुई इस मुलाकात में अभाविप के प्रतिनिधि-मंडल ने छात्रहितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर 34 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा। इन मांगों में प्रमुख रूप से विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहे छात्रों के उत्पीड़न, पब्लिक स्कूलों में बढती फ़ीस, उच्च शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षण-संस्थानों में कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता, शिक्षक-भर्ती में पूर्ण रूप से यूजीसी की गाइडलाइन का अनुपालन, विश्वविद्यालयों में छात्रों के समुचित समायोजन हेतु प्लेसमेंट सेल सहित अन्य कई मांगें शामिल हैं।

अभाविप के संयुक्त क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा-व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा रही है। शिक्षा, जो किसी समाज या राज्य के विकास की आधारशिला होती है, को सुदृढ़ करने के लिए उसके तह तक जाना अनिवार्य है। मानवीय संसाधन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। फिर भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा-व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है।

आपको बता दें कि अभाविप ने अपने मांगपत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मांग की है कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या का स्थायी समाधान तुरंत किया जाए तथा शैक्षिक सत्र नियमित करने के साथ ही शैक्षिक सत्रों के सुचारू संचालन के लिये संयुक्त शैक्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। वर्ष में 180 दिन पढाई हो तथा परीक्षा से एक माह के भीतर परीक्षाफल घोषित किए जायें। इसके अलावा छात्र संघों को बहाल करते हुए लिंगदोह-समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र संघ-चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाएँ जैसे मुद्दों को भी मांगपत्र में गंभीरता से उठाया गया। वहीं, शोध-शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु राज्य के समस्त शोध-छात्रों को नियमित रूप से दस हज़ार मासिक छात्रवृत्ति सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की है।

अभाविप के प्रतिनिधिमडल में संयुक्त क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मपाल, अखिल भारतीय प्रकाशन एवं प्रशिक्षण प्रमुख मनोजकांत, रमेश गड़िया, मनोज निखरा, सुनील वार्ष्णेय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमण्डल से मिलकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अतिशीघ्र इन मुद्दों पर विचार करते हुए शैक्षिक स्थिति को सुधारने का आश्वासन दिया।

प्रिय मित्रो !
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का मई, 2017 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह अंक जम्मू काश्मीर, आतंकवाद, विभिन्न विषयों के साथ-साथ विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए है। आशा है, यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें :

संपादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
'छात्रशक्ति भवन', 26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002.
फोन : 011-23216298
वेबसाइट : www.abvp.org
chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

On the Verge of War : North Korean Missile Crisis

■ Dr. Abhishek Srivastava

Since many years, North Korea has made a steady progress in its nuclear and missile programmes. On October 9, 2006, North Korea announced that it had conducted its first test of a nuclear weapon. At that time, The United Nation Security Council (UNSC) imposed weapons and financial sanctions on North Korea. The UN Resolution 1718 demanded that "North Korea conduct no additional nuclear test or launch ballistic missiles, rejoin the NPT and abandon all nuclear weapons and existing all nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner". North Korea has always resisted the US counter-proliferation efforts and their 'self-inspector' attitude. Again, in 2013, nuclear tests were conducted and twice in last year. It is estimated that North Korea has enough fissile material for 10 to 15 nuclear devices. By 2019, North Korea will be able to develop long-range missiles that can reach the U.S. mainland.

The ongoing hostility between the two countries remains largely a product of Cold War politics. There were conflicts and animosity between the two ideological blocs, *i.e.* United States of America and North Korea. In the mid-19th century Korea stopped cooperating with Western countries. After the 'General Sherman incident' Korean forces attacked a United States gunboat and in retaliation U.S. attacked on the Shinmiyangyo, which had further fuelled the tension. In recent times, tensions between the United States and the North Korea have risen sharply in as a series of North Korean missile tests.

Historically, the US- North Korean relationship was always bitter. In 1953, the 'Korean War' ended in a ceasefire but a treaty officially ending the war has never been signed. The North Korea remains one of the world's most dangerous flashpoint. In fact, the Korean War has globalized the Cold War. During the50's in the last decade, these circumstances propelled the US in the direction of militarizing the containment doctrine. To this end, events in Asia brought about a dramatic increase in US military spending and transformed NATO from a political grouping into military alliances.

The North Korea's situation stands as perhaps Trump's most pressing international concern. After assuming office, as he looks to

notch legislative achievements in Washington on health care and tax reform, these two goals eluded him during his first 100 days. On Capitol Hill, the House of representative plans to debate and vote on a new North Korea sanctions bill this week. Few days ago, with international support, the Trump administration said that they want to exert a "burst" of economic and diplomatic pressure on North Korea that yields results within months to push the communist government to change course from developing nuclear weapons.

Last month Trump had ordered a missile attack on Syrian airbase to retaliate for Syria's use of chemical weapons on civilians. Tensions with North Korea had ratcheted up over that nation's rocket tests. Now, America is butting heads in Syria with Russia, the other great nuclear power and we are watching the range of North Korean nuclear missiles stretch inexorably toward Seattle. The U.S. said it would dispatch an aircraft carrier, and North Korea said it could sink such a ship. According to a Public Policy Polling survey taken last month, 39% of all voters (and two thirds of Clinton voters) think Trump will get the U.S. into World War III during his presidency. Last week Trump said a "major, major conflict" with North Korea was possible. Asked on CBS' *Face the Nation* whether the U.S. might use force to stop North Korea's program, he only said, "We'll see". Susan Thornton, the acting top U.S. diplomat for East Asia, said that military action remains possible. The Trump administration treats North Korea as its primary security challenge and is serious that "all options are on the table". The Secretary of State Rex Tillerson said that "We do not seek regime change in North Korea. ... What we are seeking is the same thing China has said they seek "a full denuclearization of the Korean peninsula". Again Tillerson mentioned that, the United States needs to separate its values from its policies. For the sake of national and regional security, curtailing Pyongyang's weapons program is clearly the higher priority. However, the leaders of the United Kingdom and Japan, speaking at a joint conference in Britain, echoed Mr Tillerson's concerns. "North Korea's missile tests are a threat to global peace and security and Britain will work with international partners to maintain pressure on Pyongyang," Prime Minister of United Kingdom Ms. Theresa said. "In the face of this belligerence, we stand steadfast in our condemnation of such destabilising activity." Ms Theresa also reiterated her support for working with the international community to resolve the issue. Japanese Prime Minister Mr. Sinzo Abe said that "we will continue to work with our international partners to maintain pressure on North Korea and counter the security threat posed by its illegal pursuit of nuclear options and work towards a peaceful resolution". The hard stance on North Korea's nuclear testing was not praised by all of the international community. However, Russian deputy foreign minister Gennady Gatilov warned that an escalation to violence would be "completely unacceptable".

The combative rhetoric coupled with reckless muscle-flexing has led to a situation where the whole world seriously is now wondering whether there's going to be a war or not. In this global scenario, there is a vital role for major power like China and Russia to play, both of whom are neighbours of North Korea with influence on Pyongyang, and as permanent members of this council. They have a special responsibility for preserving international peace and security. The Trump administration should prefer multilateral approach to manage this conflict while emphasizing a "smart power" approach that attempts to integrate diplomatic and international development tools for promoting regional stability, security and peace.

(Writer is Ph. D. in International Politics from Jawaharlal Nehru University, New Delhi)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के ख़िलाफ़ अभाविप ने सौंपा ज्ञापन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के तानाशाही रवैये के ख़िलाफ 2 मई को अभाविप के प्रतिनिधि मंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ज्ञापन सौंपा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कई दिनों से कुलपति के तानाशाही व छात्रविरोधी निर्णयों के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे अभाविप के अखिल भारतीय मीडिया एवं जनसंपर्क प्रमुख श्रीरंग कुलकर्णी ने बताया कि इन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा छात्रों की आवाज़ को बलपूर्वक दबाया जा रहा है। कुलपति अपने पद के मद में इस कदर चूर हैं कि छात्रों द्वारा चुने गए छात्रसंघ-प्रतिनिधि की भी बात नहीं सुन रहे हैं। इतना ही नहीं प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्रा सहित 22 अन्य छात्रों को पुलिस-प्रशासन की मदद से जेल भिजवा दिया।

अभाविप ने अपने मांगपत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग की है जब तक इन सभी मुद्दों पर जांच कमेटी गठित कर जांच पूरी नहीं होती है, तब तक कुलपति महोदय को छुट्टी पर भेजा जाये। अभाविप प्रतिनिधि मंडल ने अपने ज्ञापन के साथ ही कुलपति द्वारा लिए गए गलत निर्णय की विस्तृत रिपोर्ट, छात्रसंघ अध्यक्ष का मांगपत्र, समाचार-पत्रों की प्रतियाँ भी सौंपी। प्रतिनिधि मंडल में अभाविप के अखिल भारतीय मीडिया एवं जनसंपर्क प्रमुख श्रीरंग कुलकर्णी, साकेत बहुगुणा, आलोक पाण्डेय, मोनिका चौधरी, आनन्द श्रीवास्तव, अमित तँवर शामिल रहे।

अभाविप की मुख्य मांगें

- मुद्दों पर जांच कमेटी गठित कर जांच जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक कुलपति महोदय को छुट्टी पर भेजा जाये।
- छात्रों पर लगे झूठे मुक़दमे वापस लिए जाएँ।
- परीक्षा होने तक सभी छात्रों की छात्रावास में भर्ती की जाए।
- पिछले सालभर के व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।

ABVP gave memorandum to HRD Minister regarding Punjab University

For many weeks now, ABVP has been protesting the unfair and exorbitant hike in fees in Punjab University. The fee hike has come after the Central government's denial to increase the grants for Punjab University by 10-12 per cent every year, like other centre-sponsored universities.

The University's funds are now fixed at 176 crores annually. Even the state government of Punjab has denied giving any financial assistance to Punjab University. Due to this, deficit of university is increasing every year.

Therefore, to meet the expenses, Punjab University's Vice Chancellor, Senate and Syndicate have increased the fee of students by many folds on the grounds of not receiving any extra grants, neither from the Punjab government nor from Central Government. The authorities of Punjab University have termed this fee hike as the last resort.

The fee hike is enormous and beyond the reach of most of the students. For example, fee of some courses has been increased from Rupees 4000 to 50000, 9400 rupees to a massive 1 lakh rupees. In all the cases the minimum fee hike is more than 100 percent. As a consequence of this fee hike all student organizations are protesting against the authorities. Taking benefit of the situation, some opportunists are intentionally spreading violence on the campus.

Punjab University has been facing financial crunch for more than two decades but no permanent solution has been kept in place to tackle it. So in this light, ABVP also holds the viewpoint that University should be given the status of central university. It should also be noted here that in 2015, ABVP unit of Punjab University had given a representation to Ministry of Human Resource and Development regarding financial bungling going on in the university. After their complaint, UGC formed a fact finding committee but its report was not given in public.

ABVP Demands

- Issues between UGC and Punjab University should be resolved in a speedy manner either in the court or at the government level but the grant should not be stopped on this ground.
- Pending Grant should be released immediately.
- MHRD should issue directions to University authorities to roll back massive fee hike
- Report of that fact finding committee formed by UGC on complaint of ABVP in Year 2015 should be made public and a criminal case should be registered against Vice Chancellor and others who are involved.
- MHRD should form a High level committee to conduct an inquiry on Anti- National activities going on in University.
- Government of India should give central status to Punjab University so that financial crunch of university can be solved permanently.

ABVP organises 'SAMAJIK ANUBHUTI' in Telangana

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and Students for Development (SFD) jointly organised "SAMAJIKA ANUBHUTI"- state level social survey in all ten districts of Telangana state. In this survey, hundreds of students from various disciplines like Degree, PG, Engineering, Research Scholars and other professional courses participated.

The objective of the programme was to sensitize the student community on serious social problems, to provide them an opportunity to study the reasons associated with social problems in Telangana and motivate them to work independently on social issues, to identify the socio-economic status and demographics of victims or respondents, to generate an future agenda for social organizations and NGOs where they can contribute and to play an advocacy role with governments (state/central/local) for the solution of the selected social problems.

Across several districts of Telangana, several issues/challenges were identified including problems of footpath dwellers in government & private hospitals, slum dwellers, Adda Kulilu (daily base labour), child labour, labour demographics in Katedaan, migration, child marriages, Jogini System, female foeticide, baby selling in tribal areas, seasonal diseases in tribal areas and , several other tribal issues, conversions, Coal mining labour issues, Bhunirvasitulu, weavers' issues, gulf Victims and Beedi workers.

For identification of the mentioned issues, experts working in NGOs and service sector were consulted after which the ABVP state working committee finalized issues to initiate the survey state wide. Several base camps were established on the basis of issues for conduction of the survey. Almost 330 student volunteers participated in this social survey through twenty base camps in different locations including rural, urban and tribal areas. More than 1100 families and 26000 individuals responded to the survey. ■

अभाविप के कार्यकर्ताओं ने किया सामाजिक जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, राजस्थान प्रान्त की ओर से 'सामाजिक अनुभूति : 2017' के प्रथम चरण का आयोजन बेहद उत्साहपूर्वक किया गया। अभाविप के प्रदेश-अध्यक्ष आनन्द पालीवाल ने बताया कि राजस्थान प्रान्त के 3 संभागों (जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़) में 10 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य प्रथम चरण का आयोजन किया गया। इसमें पूरे प्रान्त के 2081 विस्तारकों ने 19,633 परिवारों तक सम्पर्क किया। इस चरण में राजस्थान प्रान्त से 1854 छात्र, 192 छात्राओं, 36 शिक्षकों ने विस्तारक के रूप में भाग लिया। विस्तारकों ने गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी व कच्ची बस्तियों तक पहुँचकर सामाजिक जीवन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हर समस्या को प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इस दौरान उन्होंने अनुभव किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि कुछ ऐसे गाँव हैं, जो आधुनिकता के दौर में अपने आप को समायोजित कर चुके हैं। ग्रामीण परिवेश के युवा आज भी नशाखोरी, बेरोजगारी-जैसी गम्भीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। विस्तारकों को प्रथम दिन सभी प्रशिक्षण-केन्द्रों पर दिनभर का प्रशिक्षण दिया गया एवम् इसके बाद तय उपकेन्द्रों पर रवाना किया गया। विस्तारक लगातार 4 दिनों तक गाँवों में, ढाणियों में, कच्ची बस्तियों में घूम-घूमकर वहाँ की वास्तविकता से रूबरू हुए। सभी विस्तारकों का रात्रि-निवास उपकेन्द्रों पर किया गया, जिसमें सभी विस्तारकों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव बताये, साथ ही प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध भी किया गया है और स्वयं के स्तर पर इनके समाधान की योजना भी अभाविप-कार्यकर्ताओं ने बनाई। आनन्द पालीवाल ने बताया कि सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है? इसके लिए मेडिकल और तकनीकी से जुड़े छात्रों को भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि विस्तारकों की उत्साहपूर्वक संख्या को देखते हुए दूसरे चरण की योजना अभी से प्रारम्भ कर दी गई है। ■

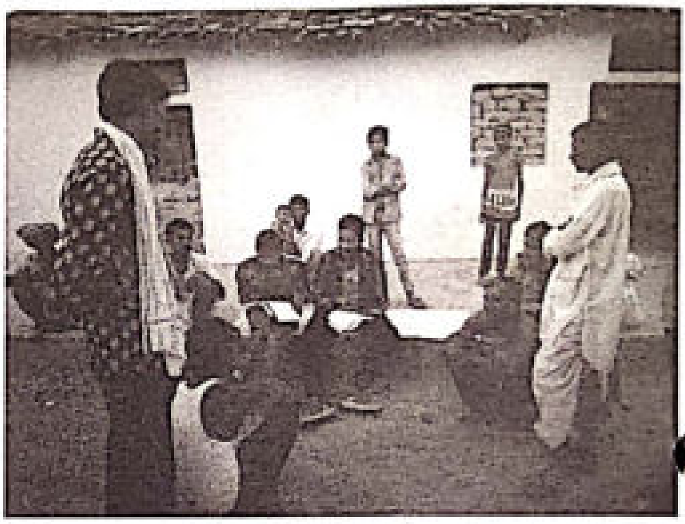

बीआईटी परिसर में 'छत्तीसगढ़ युवा संसद' का शानदार आगाज़

बीआईटी कॉलेज, दुर्ग (छत्तीसगढ़) में 22 अप्रैल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के आयाम 'थिंक इण्डिया' और 'आई फर्स्ट' के बैनर तले 'छत्तीसगढ़ युवा संसद' का आयोजन किया गया। आयोजन का मकसद युवाओं में नीति-निर्माण, संसदीय कार्य प्रणाली एवम् राजनीतिक जागरुकता को बढ़ाना था। इस युवा संसद में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनन्दगाँव, रायपुर और कवर्धा ज़िले के 150 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। तीन सत्रों में चले युवा संसद में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

पहले सत्र में 'राष्ट्रवाद : एक सच्ची परिभाषा', दूसरे सत्र में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर युवाओं का एक सर्वमान्य विचार, तीसरे और अंतिम सत्र में अनुच्छेद-370 विषय पर पक्ष-विपक्ष में चर्चा हुई। अभाविप का मानना है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से छात्र वर्तमान के भारत की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों व मुद्दों से रूबरू होते हैं।

युवा संसद के इस आयोजन में प्रदेश पदाधिकारी तथा अभाविप के समस्त ज़िला-प्रतिनिधि मौजूद रहे। सत्र के अन्त में सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र और स्मृति-चिह्न भेंट किए गए। ■

Growing Naxalism and its Urban Connect

■ Abhishek Tandon

Naxal, Naxalism, Naxalites, Maoism, Maoist , Red Terror , Left Terror and many of their synonyms; we all have got used to hearing these words. Aren't we? We feel helpless for innocent people and our armed forces but forget about them the moment the news disappears from breaking news or first page . However on 24th April when I heard of killings of 24 CRPF jawans by Maoists in Sukhma I got traumatized. I still remember I could not sleep for the entire night and just kept on changing various news channels so that I could get an idea of the ground report. Most of the news channels had spokespersons of political parties accusing each other of action taken by the government. Some had retired army staffs that were demanding for strong reply by the government. However none deliberated on the real cause of this horrendous act.

Naxalism or Maoism is prevalent in parts of Chhattisgarh, West Bengal, Jharkhand, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa and Telangana.

Naxalism is purely terrorism and nothing else. We need to understand this very clearly that we will have to do away with old definitions given to Naxalism by some scholars. Henceforth Naxalism is "the unlawful use of violence and intimidation, against civilians and army men, in the pursuit of political aims". But the bigger question is why Naxalism? The answer to this question is urban and intellectual terrorism to destroy the integrity of India in the name of autonomy. A class of pseudo intellectuals or so called social workers is working actively in connivance with external forces to destroy the integrity of this country. Sources from the internet and television confirmed that villagers living near Sukhma, Dantewara and tribal areas in Bastar denounce violence and want to work constructively with the state. But the villagers are continuously harassed by these insurgent groups. There women are raped by Naxalites in front of the villagers, they eat human flesh, bodies are being mutilated, men are killed in front of their wives and children If the villagers try to raise their voice or seek help from the government their atrocities and killings multiply. This is done with a definite design to separate a particular area or population from India's governance. We have already heard slogan like *'Bastar ki Azadi tak Zang Rahegi'*. However, the *azadi* or so called autonomy that's being demanded is on pretext of schedule 5 and 6 of the constitution. This schedule is completely misunderstood and misrepresented as it talks about cultural autonomy of tribes and their practices. But what's interesting is that people who have taken the route of violence are people from the tribes, forests who lack complete knowledge of the constitution and its schedules. This clearly indicates two things ; firstly that this movement is lead by people who are intellectuals and keep visiting these areas in the name of research, media activism , human rights , social activism and secondly they have funding from foreign states. In 2011, Indian police accused the Chinese government of providing sanctuary to the move-

ment's leaders, and accused Pakistani ISI of providing financial support. The reason for this is empirical as people who have chosen the path of violence are brainwashed completely in the name of autonomy, their rights for land, and their rights for resources. However they are not taught about the positives development and state can bring about in their life. These people know how to use guns and make bombs but don't know how the route of development is beneficial for them. Unfortunately, people who try to understand and spread the message of development are killed or are threatened by the social workers, NGOs,Researchers and Professors in the area. Vinita Baghel, alleged that a fact-finding team that included Delhi University Professor Nandinai Sundar, JNU Professor Archana Prasad and CPI (M) leader Parate had warned her husband, Samnath Baghel, not to oppose the Maoists. Samnath Baghel was killed by Maoists on the night of November 4 in Nama village of Sukma district. He was dragged out of his house while Vinita, who was with their four-day-old son, watched reported Indian Express. Media has also reported suspicion over human right activist Bela Bhatia's role in misleading people and supporting maoists. Villagers have asked her to move out of Chhatisgarh on several occasions. Interestingly, the same people and people belonging to the same ideology condemn 'Violence in all forms' sitting in Delhi. It's hard to understand why there's so much difference in their ideology when they travel from Delhi to Chhattisgarh. Reports from the press clearly indicate that people travel to the affected areas and provide help to the Naxalites to act against the local villagers and armed forces. Interestingly, Maoist killed 24 CRPF jawans when they were guarding construction of 5.5 Km long road. Hence, the message is loud and clear no development work should be carried out in the area where Maoists are operating. Because if development process is seen and common villagers are connected with mainstream, then urban intellectuals and tribal terrorists would become insignificant.

Around twenty thousand people have been killed in the last two decades because of naxalism. Various governments at centre have launched various development plans in areas affected by left extremism. But still there is lot to be done so that the innocent villagers and brave army men are not killed by rebellious groups. Who will save their human rights? Whether NHRC has ever enquired about human rights of 24 people killed in Sukhma? These questions need to be answered as well. Indeed a 360 degree approach needs to be developed and implemented in the left extremism affected areas so that they can be wiped out soon. However an even better and effective approach needs to be followed in the universities where these ideas are developed. A constant review of syllabi and research guidance needs to be done by the regulator so that no such approach is followed by any mentor/guide or teacher which can question the integrity of our country. I always maintain that social science should be taught to solve social problems and not only to create social activists. We all face confrontation with the system and feel like justice is not happening at least once in our lifetime. This is the time when we need to follow and read our constitution and act accordingly. Taking law in our hand never delivers justice and autonomy.

It's time to act swiftly and end violence in all parts of the country whether it's virtual, intellectual violence or real violence. India is fastest growing economy and it's time that the each and every citizen enjoys the fruits of hard work put in by our forefathers for years. The youth of this country which accounts to 65 % of the countries populations needs to step up and choose development and progress. The path of development will also help in improving the socio-economic and cultural issues faced by our country.

(Writer is Assistant Professor in Delhi University)

आप के पतन की बुनियाद में अरविन्द का अहंकार

जिस भ्रष्टाचार-विरोधी, ईमानदार नेता की छवि को लेकर अरविन्द भारतीय राजनीति में विकल्प के तौर पर दिख रहे थे, वह ध्वस्त हो गई है।

■ हर्षवर्धन त्रिपाठी

अरविन्द केजरीवाल ने देश की राजनीति में चमत्कारी बदलाव किए। ऐसे चमत्कारी बदलाव कि अरविन्द से लोगों ने देश की चमत्कारिक तौर पर बदलने की उम्मीद भी लगा ली। इन उम्मीदों के पहाड़ पर चढ़ते चले गए अरविन्द केजरीवाल को ये लगने लगा कि देश में जो कुछ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, वह अरविन्द ने ही पहली बार किया है। उन्हें लगा कि जनता ने उन्हें न भूतो न भविष्यति नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। और इसने अरविन्द केजरीवाल का अहंकार बहुत बढ़ा दिया। इस हद तक अरविन्द यह भी भूल गए कि आम आदमी पार्टी जिस भी स्वरूप में सत्ता तक पहुँची, उसमें बहुतेरे लोगों, संस्थाओं का योगदान है। दरअसल अरविन्द को जाने-अनजाने इस बात का अहंकार हो गया था कि उनकी निजी छवि इतनी बड़ी है कि उसमें उनकी या उनके आसपास के लोगों की सारी गलतियाँ दब जाएँगी। अरविन्द का ये अहंकार होना स्वाभाविक ही था। भारतीय राजनीति के इतिहास में एकाध मौके को छोड़कर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मात्र 2 साल में कोई पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुँच जाए। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आन्दोलन में अरविन्द अकेले नायक नहीं थे। शान्ति भूषण, उनके बेटे प्रशान्त भूषण, योगेन्द्र यादव, आनन्द कुमार, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी-जैसे लोग अन्ना की अगुवाई में चल रहे भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन में अरविन्द के साथ दूसरी कतार में साथ खड़े दिखते थे। किरण बेदी तो कई बार अरविन्द से थोड़ा ऊपर ही दिखती रहीं। लेकिन, अरविन्द को कतई यह पसन्द नहीं था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो रहे भारत के इस सबसे बड़े आन्दोलन में नेता के तौर पर उनके अलावा किसी और की पहचान हो। यह भी तय था कि अरविन्द शुरू से ही इसे राजनीतिक आन्दोलन की तरह चलाना चाहते थे। इसीलिए जब अन्ना के इनकार करने के बाद भी अरविन्द नहीं माने, तो पार्टी बनने से पहले ही आधी हो गई थी। अरविन्द दिल्ली में चुनाव लड़े और पहली बार में ही सत्ता के एकदम नजदीक पहुंच गए और फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी बना ली। लेकिन, वह सरकार ज्यादा समय तक चली नहीं। और अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार के बिना दिल्ली नहीं बदली जा सकती। दिल्ली की जनता ने अरविन्द को वह जनादेश दे दिया जो भारतीय इतिहास में किसी को नहीं मिला। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की हो गयीं। हालांकि, चुनावों के समय टिकट बँटवारे को लेकर योगेन्द्र यादव और प्रशान्त भूषण ने कई दागी प्रत्याशियों पर एतराज़ किया था।

लेकिन, अरविन्द तो अहंकार के साथ ही आगे बढ़े थे। वह अहंकार, जो किसी पर भी आरोप लगाकर जनता का साथ हासिल करने से मिला था। फिर वह भला किसी की क्यों मानते।

अरविन्द इस बात को भी भूल गए कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के वह अगुवा बनकर सत्ता तक पहुँचे, उस लड़ाई को 2011 में ही नहीं शुरू किया गया। अन्ना हजारे-जैसे समाजसेवी उसे अलग-अलग समय पर लगातार उठाते रहे। यहाँ तक कि जिस लोकपाल की बात आज जोर-शोर से हो रही है, उसकी पहली चर्चा दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने ही की थी। आपातकाल के तुरन्त बाद हुए जयपुर के अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद ने लोक अभियान की शुरूआत करने पर जोर दिया था। 1994 के इन्दौर-अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद् ने बाकायदा भ्रष्टाचार पर ही अपना पहला प्रमुख प्रस्ताव पेश किया। सभी राज्यों में लोकायुक्त/लोकपाल के पद को आवश्यक तथा प्रभावी बनाने की मांग की गई। इसी प्रस्ताव में मंत्री, सांसद, विधायक के चुनाव-पूर्व संपत्ति-घोषणा, प्रतिनिधि-वापसी का अधिकार जनता को मिले, चुनाव-खर्च पर अंकुश के लिए चुनाव-प्रणाली में संशोधन और बड़े नेताओं की बेनामी संपत्ति की जाँच हेतु एक स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग की गई थी। जो बात अरविन्द 2011 में कह रहे थे, वह मांग जोर-शोर से विद्यार्थी परिषद् ने 1994 में उठाई थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में धीरे-धीरे किसी बात पर जनमत तैयार होता है। और वर्षों से चल रही इस मांग पर जनमत 2011 के बाद तैयार हुआ। लेकिन, अरविन्द को यह अहंकार हो गया कि सब उनका अकेले का और अभी का ही किया हुआ।

जिस लोकपाल की बात आज जोर-शोर से हो रही है, उसकी पहली चर्चा दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने ही की थी। आपातकाल के तुरन्त बाद हुए जयपुर के अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद ने लोक अभियान की शुरूआत करने पर जोर दिया था। 1994 के इन्दौर-अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद् ने बाकायदा भ्रष्टाचार पर ही अपना पहला प्रमुख प्रस्ताव पेश किया। सभी राज्यों में लोकायुक्त/लोकपाल के पद को आवश्यक तथा प्रभावी बनाने की मांग की गई। इसी प्रस्ताव में मंत्री, सांसद, विधायक के चुनाव-पूर्व संपत्ति-घोषणा, प्रतिनिधि-वापसी का अधिकार जनता को मिले, चुनाव-खर्च पर अंकुश के लिए चुनाव-प्रणाली में संशोधन और बड़े नेताओं की बेनामी संपत्ति की जाँच हेतु एक स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग की गई थी। जो बात अरविन्द 2011 में कह रहे थे, वह मांग जोर-शोर से विद्यार्थी परिषद् ने 1994 में उठाई थी।

फिर वही हुआ, जिसका एक अहंकारी नेतृत्ववाली पार्टी में होना तय होता है। किरण बेदी तो पहले ही बाहर जा चुकी थीं। आमने-सामने की लड़ाई में किरण बेदी को बुरी तरह से हराने से बुलन्द हौसले ने अरविन्द को और अहंकारी बना दिया। अरविन्द ने दूसरी पांत की लड़ाई में अन्ना आन्दोलन के समय उनके साथ खड़े लोगों– शान्ति भूषण, उनके बेटे प्रशान्त भूषण, योगेन्द्र यादव, आनन्द कुमार को निकाल बाहर किया। इस समय की आम आदमी पार्टी देखने से साफ़ दिखता है कि अरविन्द ने उन लोगों को अब आम आदमी पार्टी का चेहरा बना दिया है, जिन चेहरों की अरविन्द के सामने कोई औकात नहीं है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, दिलीप पांडेय, कपिल मिश्रा- यही वे चेहरे हैं जो अब आम आदमी पार्टी हैं। ये अरविन्द के अहंकार को पोषित करनेवाले चेहरे हैं। मनीष सिसोदिया निश्चित तौर पर इनमें सबसे भरोसेमन्द, काम करनेवाले चेहरे हैं। लेकिन, इन लोगों को बोलते सुनकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि अरविन्द का अहंकार बढ़ाने में इन लोगों का कितना बड़ा योगदान है। इसीलिए दिल्ली से लेकर पंजाब तक जब संजय सिंह पर ढेर सारे आरोप लग रहे थे, तो अरविन्द को संजय सिंह का अपने अच्छे दरबारी की तरह खड़े रहना ज्यादा याद रहता था। पहले पंजाब और अब दिल्ली नगर निगम में जनता से नकारे जाने के बाद लम्बे समय तक अरविन्द का अहंकार उन्हें यह मानने नहीं दे रहा था कि आम आदमी पार्टी से जनता किनारे हो सकती है। क्योंकि, वह तो खुद को नरेंद्र मोदी के सामने अकेले विकल्प के तौर पर देख रहे थे। और उनके दरबारियों ने ये अहंकार हर दिन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन, जब लगा कि अब मशीन पर अविश्वास इससे ज़्यादा करना जनता की नज़रों में और गिरा देगा, तो अपने दरबार की लम्बी सलाह के बाद अरविन्द ने गलती मानी है। लेकिन, अभी भी शायद उन्हें असली गलती का अन्दाज़ा नहीं है। असली गलती है, उनका अहंकार। और अरविन्द ने गलती में अभी तक अपने अहंकार की बात नहीं की है। अब जब तक इस असली गलती को अरविन्द नहीं सुधारते, आम आदमी पार्टी पतन के रास्ते से शायद ही लौट सकें।

दिल्ली को देश की राजधानी होने से ख़ास सहूलियत मिली हुई है। यहाँ सब ख़ास होते हैं। कमाल ये कि उस ख़ास दिल्ली में आम आदमी की बात करके एक पार्टी सत्ता में पहुँच गयी। सत्ता में यूँ ही नहीं पहुँच गई, सत्ता में वह 'आम आदमी पार्टी' नाम रखकर देश की सबसे ईमानदार पार्टी होने का वातावरण तैयार करके पहुँची। इण्डिया अगेन्स्ट करप्शन के बैनर पर अन्ना को चेहरा बनाकर शुरू हुई लड़ाई से निकली पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दे दीं। 2 साल से भी कम समय के संघर्ष में ख़ास दिल्ली में राजनीति करने की वज़ह से अरविन्द केजरीवाल को देश में बदलाव के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन, पहले पंजाब, गोवा और अब दिल्ली नगर निगम के चुनाव में तगड़ी हार के बाद अरविन्द को पूरी तरह से राजनीति में बाहर होता देखा जाने लगा है। सवाल ये है कि क्या विश्लेषकों ने तब जल्दी की थी या अब जल्दी कर रहे हैं ? सवाल ये भी है कि 2011 से 2017, मात्र 6 साल में किसी व्यक्ति, पार्टी के इस तरह से सत्ता के शिखर पर पहुँचने और जनता का आकांक्षाओं पर इतनी बुरी तरह से खरा न उतर पाने का क्या ये अकेला उदाहरण है। जब इस सवाल का ज़वाब हम खोजने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं कि ये अकेला उदाहरण नहीं है। ठीक ऐसा ही एक उदाहरण भारत में ही देखने को मिला। लेकिन, वह उदाहरण देश के पूर्वोत्तर राज्य से आता है, इसलिए उस पर उतनी चर्चा देश में नहीं हुई।

अरविन्द की आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलने में 2 साल से भी कम का समय लगा। हालांकि, 6 साल से भी कम समय में पराभव की भी बड़ी कहानी लिखी जा चुकी है। लेकिन, अरविन्द और उनकी आम आदमी पार्टी से भी 3 दशक से ज़्यादा पहले असम में भी ऐसी ही चमकदार कहानी लिखी गई थी। छात्र संघों से निकले नेताओं की पार्टी बनी थी– असम गण परिषद्। छात्रों ने ऑल असम स्टूडेण्ट्स यूनियन बनाकर 1979 से आन्दोलन करना शुरू किया। आन्दोलन का मुद्दा था असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करना, उनका नाम मतदाता-सूची से बाहर करना। इसी आन्दोलन के दौरान 1983 में असम में चुनाव हुए और कांग्रेस के हितेश्वर सैकिया मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन, ऑल असम स्टूडेण्ट्स यूनियन ने ऑल असम गण संग्राम परिषद् के बैनर तले दूसरे संगठनों को एकजुट करके इसे मानने से इनकार कर दिया। लम्बे समय तक चले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 15 अगस्त, 1985 को असम समझौता हुआ। ऑल असम गण संग्राम परिषद् में असम साहित्य सभा, असम जातीयवादी दल, पूर्वांचलिया लोक परिषद्, असम कर्मचारी परिषद्, युवा छात्र परिषद्, असम युवक समाज और ऑल असम सेंट्रल-सेमी सेंट्रल एम्प्लई यूनियन के लोग शामिल हुए थे। राजीव गाँधी के साथ आसू का समझौता हुआ और हितेश्वर

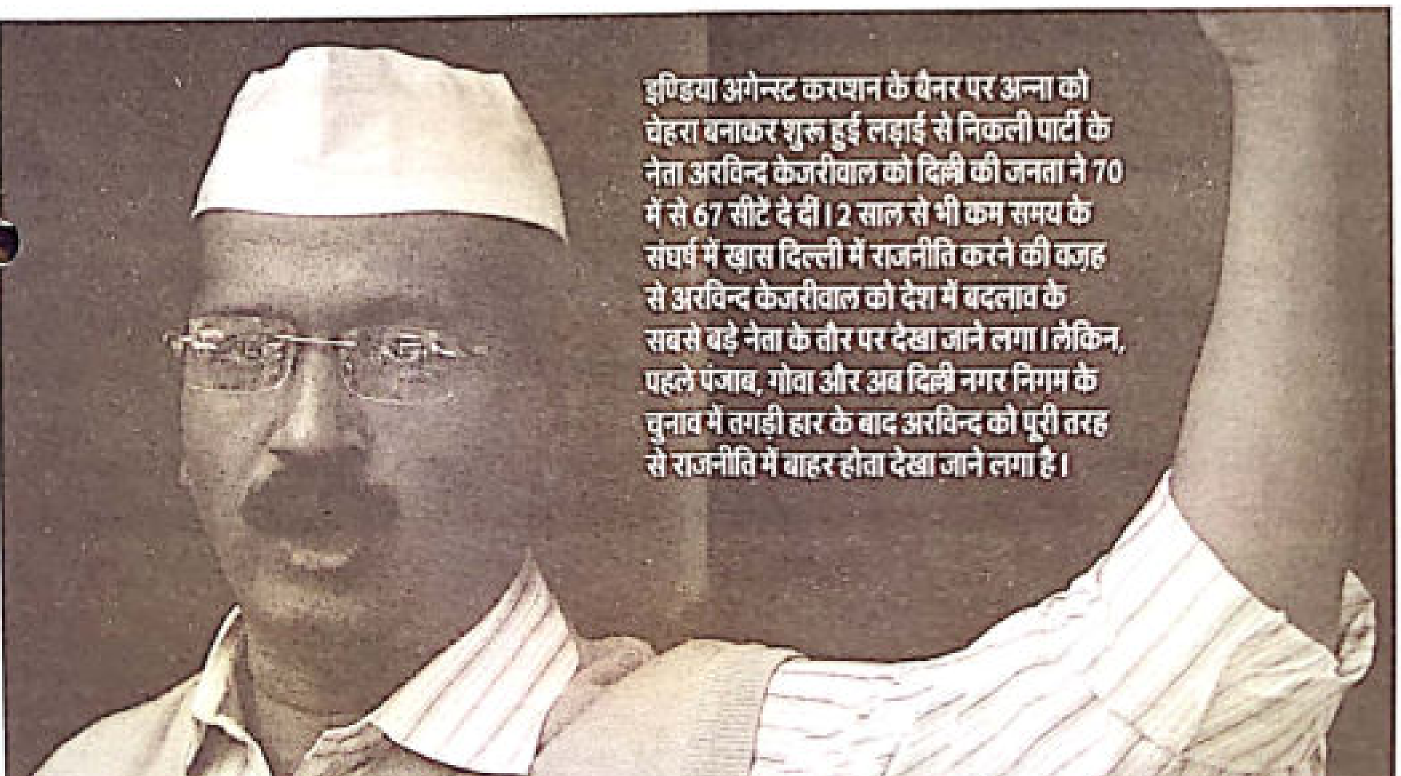

सैकिया की सरकार को बर्ख़ास्त किया गया। 14 अक्टूबर, 1985 को गोलाघाट में हुई राष्ट्रीय कार्यसमिति में बाकायदा असम गण परिषद् का एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर जन्म हुआ और आसू अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महन्त इसके अध्यक्ष बने। असम गण परिषद् ने दिसम्बर, 1985 में हुए विधानसभा-चुनावों में 126 में से 67 सीटें जीत लीं। साथ ही असम की 14 में से 7 लोकसभा सीटों से भी असम गण परिषद् के प्रतिनिधि चुनकर पहुँचे।

दिल्ली की 70 में से 67 के मुकाबले 126 में से 67 सीटें उतनी प्रभावी भले न दिखती हों, लेकिन उस समय इससे चमत्कारिक जीत लोकतंत्र में नहीं हुई थी। कुछ समय पहले बनी पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली थी। मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महन्त सहित ज़्यादातर मंत्री और विधायक छात्र संघों के प्रतिनिधि से सीधे जनप्रतिनिधि बन गए थे। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए 5 साल चली। लेकिन, 5 साल बाद हुए चुनाव मेंअसम गण परिषद् सत्ता से बाहर हो गई। 1991 में भृगु कुमार फूकन के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश गोस्वामी, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बृंदाबन गोस्वामी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पुलकेश बरुआ ने मिलकर नयी असम गण परिषद् बनाकर चुनाव लड़ा। 1992 में ये लोग फिर पार्टी में आ गये। लेकिन, पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महन्त पर गम्भीर भ्रष्टाचार और राजनीतिक विरोधियों की हत्या तक के आरोप लगे। पूर्ण बहुमत से दिसम्बर 1985 में सत्ता में आई असम गण परिषद् को 1991 में सिर्फ़ 19 सीटें मिलीं। खुद प्रफुल्ल महन्त 2 सीटों से लड़े, लेकिन एक ही सीट से जीत पाए थे। कॉंग्रेस 66 सीटों के साथ सत्ता में लौटी थी। भाजपा के 10 विधायक चुनकर आए थे। असम गण परिषद् से टूटकर बनी एनजीएपी के भी 5 विधायक चुनकर पहुँचे थे। हालांकि, 1996 में फिर से संयुक्त असम गण परिषद् में सत्ता में आ गई। असम गण परिषद् के 59 और कॉंग्रेस के 34 विधायक जीते थे। 2001 से 2016 तक लगातार तीन बार कॉंग्रेस के तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहे। 2016 में भाजपा पहली बार असम में सत्ता में आई और सर्वानन्द सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। असम गण परिषद् केवल 10 सीटें हासिल कर सकी।

दिल्ली नगर निगम चुनाव-परिणामों के बाद जब देश आम आदमी पार्टी की समीक्षा कर रहा है, तो मुझे असम गण परिषद् की कहानी इसीलिए कहना ठीक लगा। आम आमी पार्टी नगर निगम चुनाव के बाद ख़त्म हो गई, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन, इतना तो ज़रूर है कि जिस ऊँचे, भ्रष्टाचार-विरोधी, ईमानदार नेता की छवि को लेकर अरविन्द भारतीय राजनीति में विकल्प के तौर पर दिख रहे थे, वह ध्वस्त हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे अमस गण परिषद् ने खुद को असम के हितों को एकमात्र चैम्पियन घोषित कर लिया था। असम गण परिषद् में एक बार 5 साल की सरकार चलने के बाद टूट शुरू हुई थी। अरविन्द ज़्यादा तेजी से सत्ता तक पहुंचे थे, इसलिए इसकी जरा-सी भी मलाई वह दूसरे महत्त्वाकांक्षी नेताओं को नहीं दे सके। नतीज़ा योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनन्द कुमार-जैसे नेता शुरूआत में ही किनारे हो गए। 'स्वराज इण्डिया' नयी पार्टी बन गई और निगम चुनाव भी लड़ गयी। अब फिर से आम आदमी पार्टी बाहर गए नेताओं पर थोड़ी नरम दिख रही है। हो सकता है कल को दोनों कमज़ोर होकर एक भी हो जाएँ। अरविन्द ने विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर लाभ दे दिया। 21 विधायक अयोग्य हो गए तो, दिल्ली विधानसभा की शक्ल बदल सकती है। अरविन्द पर नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के जमकर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी ठीक उसी रास्ते पर जाती दिख रही हैं, जिस पर चलकर असम गण परिषद् आज 126 विधायकोंवाली असम विधानसभा में 10 सीटों पर सिमट गई है। हाँ, अब यह ज़रूर देखने की बात होगी कि क्या अरविन्द को आम आदमी पार्टी से निकालने की ताक़त किसी नेता ने बना ली है। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए दिखता है; क्योंकि असम गण परिषद् छात्र आन्दोलन से निकली पार्टी थी, जिसके नेता छात्र संघों से संघर्ष करके आए थे, यहाँ आम आदमी पार्टी ढेर सारे एनजीओ को जोड़कर बनी है। इसलिए एनजीओ एक्टिविस्टों से ऐसी उम्मीद मुझे थोड़ी मुश्किल दिखती है। कुल मिलाकर अरविन्द केजरीवाल अभी भी नहीं सुधरे तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में असम गण परिषद् की राह पर जाती दिख रही है। और इतनी बुरी हार के बाद भी ईवीएम में गड़बड़ी चिल्लाकर अरविन्द मेरी कही बात को सच करते दिख रहे हैं। आख़िरकार काफ़ी ज़द्दोजहद के बाद अरविन्द केजरीवाल ने यह मान लिया है कि उनसे ग़लतियाँ हुई हैं। अब ग़लतियों को सुधारकर वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन, सवाल जस-का-तस बना हुआ है कि क्या अरविन्द को सच में अपनी ग़लतियों का अहसास हो गया है। क्या अरविन्द केजरीवाल अपनी सबसे बड़ी ग़लती यानी अपने अहंकार को सुधारेंगे, उसे कम करेंगे? आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य अब इसी पर टिका हुआ है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

ABVP protests against Karnataka government's failure to tackle Law and Order

ABVP Karnataka organised a protest against the state government's misuse of government machinery and complete failure of law and order.

In many districts including Udupi, Bagalkot, Mangaluru and Koppal, the sand mafia is very active. Local politicians are often found supporting the mafia. This is also one of the reasons why many honest and hard-working officers are attacked by goons. These officers are always under stress since they do not have free space to work. Those who are dedicated and fulfil their duties sincerely are transferred. So ABVP decided to protest against Karnataka government, urging it to maintain law and order and prevent harassment of the honest officers.

In Hubballi, the protest was led by ABVP National Secretary Sri. Vinay Bidre, State Secretary Sunil Prasad and State Joint Org Secretary Laveen Kotiyan led the protests in Bengaluru and Mangaluru respectively.

In the protest, ABVP also raised its voice against the increasing incidents of rape and atrocities against women and children. ABVP demanded that all the culprits receive punishment in a way that acts as a deterrent against such acts of violence in the future. The protest was organised in as many as 73 districts and saw participation of almost 50,000 people from 22 regions of the state.

परिचर्चा

महापुरुषों के नाम पर अवकाश कितना सही ?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अप्रैल, 2017 को लिए गए एक अहम फ़ैसले में महापुरुषों के नाम पर उत्तर प्रदेश में होनेवाली 15 छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। प्रदेश-सरकार के इस फ़ैसले को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इन छुट्टियों को सार्वजनिक अवकाश की सूची से हटाकर निर्बन्धित अवकाश की सूची में शामिल कर दिया गया अर्थात् 15 छुट्टियों के दिन सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, संस्थान, आदि खुले रहेंगे। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी के बजाय उस दिन 2 घंटे उनके जीवन पर परिचर्चा, संगोष्ठी या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य चलेगा और महापुरुषों की जयन्ती या पुण्यतिथि पर दो-दो घंटे का आयोजन कर छात्रों को उनके व्यक्तित्व व कृतित्व से अवगत करवाया जाएगा। प्रदेश-सरकार का यह मानना है कि अवकाश-संस्कृति के चलते न तो कार्य पूरा हो पाता है, और न ही अध्यापन। अधिक-से-अधिक कार्य करने व सुचारू रूप से शैक्षणिक व्यवस्था के संचालन हेतु योगी-सरकार के इस निर्णय पर क्या है आम लोगों का नज़रिया ? इस फ़ैसले पर जनता की राय जानने के लिए 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के संवाददाता उत्कर्ष श्रीवास्तव ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत युवाओं से बात की और उनके विचार जाने।

महापुरुषों का स्मरण करने की बजाए उनके नाम अवकाश घोषित कर देना , ये परंपरा-सी चल रही है। इसका उपाय करना बहुत जरूरी है । महीने में 4 से 5 रविवार और 3 से 4 जयंती या पुण्यतिथि पड़ती है । 30 दिन के महीने में यदि 8 से 10 दिन छुट्टी रहेगी, तो देश तरक्की कैसे करेगा।

—अरुण कुमार भारती, एडवोकेट, सुल्तानपुर

आज स्थिति यह है कि सरकारी दफ़्तरों में लोग काम नहीं करना चाहते। अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, जयंती के होने के कारण से जो काम एक दिन में होता है, उसे दस दिन में करते हैं। योगी सरकार ने सुधार करने का सही तरीका खोजा है। यह कदम बिलकुल सही है।

—स्वप्निल सिंह, एमए, इलाहाबाद

शिक्षण संस्थानों में 180 दिन पढ़ाई हो, यह लागू करना अभी तक संभव नहीं था क्योंकि राजपत्रित अवकाश के साथ स्थानीय अवकाशों, जैसे– जयंती, पुण्यतिथि, उर्स, पूर्णिमा, आदि की संख्या बहुत अधिक थी। शिक्षण-कार्य निरंतर व निर्बाध हो, इसके लिए कार्यदिवस भी अधिक होने चाहिए। इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र में कुछ सुधार ज़रूर होगा।

—स्नेहलता सिंह, बीए तृतीय वर्ष, बलिया, उत्तरप्रदेश

समाज में छुट्टियां तो होनी ही चाहिए , लेकिन उन त्याहारों की जिसमें समाज की सहभगिता हो, जैसे– होली, दीवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूर्णिमा। समाज में जाति के आधार पर होनेवाली छुट्टियों को ख़त्म करके योगी सरकार ने समग्र विकास का मार्ग दिखलाया है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर आज इतना गिर गया हैं कि उसे उठाने हेतु कठोर से कठोर प्रयास किये जाने की और आवश्यकता है।

—श्वेता पाण्डेय, एम.टेक., नोएडा

प्रदेश सरकार यह फ़ैसला बहुत ही सराहनीय है। छुट्टियों के नाम पर राजनीतिक समीकरण साधे जाते रहे हैं । जाति, वर्ग, संप्रदाय के व्यक्ति विशेष लोगों के नाम पर की जाने वाली छुट्टियों का आम जनता से कोई ख़ास सरोकार नहीं रहता। जिनके नाम पर अवकाश घोषित किया गया था, लोग ठीक प्रकार उन महापुरुषों के नाम भी नहीं जानते । ऐसे छुट्टियों से क्या फ़ायदा होगा ? इनको बंद करना ही सही है।

—आलोक यादव, पीडब्ल्यूडी, लखनऊ

MeDeVision 2017

Union Health Minister Sri J. P. Nadda addressing the gathering

Participants of MeDeVision 2017 in D. Y. Patil University Campus, Panvel (Maharashtra)

DELDIL11533